

# उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना

### संदरभ

उदय योजना के बाद से विद्युत वितरण कंपनियों के सुवास्थ्य में सुधार दिखने लगा है।

## क्या है उदय (UDAY)?

- उदय अर्थात् उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (Ujwal DISCOM Assurance Yojana) । डिस्कॉम अर्थात् डिस्ट्रीब्यूसन कंपनीज़ ।
- इस योजना का लक्ष्य देश की विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उनका पुनरुद्धार करना तथा उनकी समस्याओं का स्थाई समाधान सुनिश्चित करना है।
- वदियत मंतरालय दवारा यह योजना उजजवल डिसकॉम एशयोरेंस योजना या उदय नाम से परारंभ की गई है।
- यह माननीय प्रधानमंत्री के सभी लोगों के लिये 24 घंटे किफायती एवं सुविधाजनक विद्युत सुनिश्चित करने के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक पथ प्रदर्शक सुधार है।

#### उदय से लाभ

- सभी के लिये सातों दिन चौबीसों घंटे बजिली।
- सभी गाँवों के लिये विद्युतीकरण।
- सक्षम उर्जा सुरक्षा।
- रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिये बिजली क्षेत्र में निवश को पुनर्जीवित करना।
- लगभग सभी विद्युत वितरण कंपनियों को लाभदायक स्थिति में लाना।
- उदय दक्षता में सुधार कर वार्षिक 1.8 लाख करोड़ की बचत करना।

## प्रमुख बद्धि

- हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों ने उज्ज्वल डिस्कॉम बीमा योजना को अपनाने के बाद सुधार दिखाना शुरू कर दिया है।
- एक आधिकारिक बयान के अनुसार, वित्त वर्ष 2016-2017 में हरियाणा में कुल वाणिज्यिक और तकनीकी घाटा वित्तीय वर्ष 2015-2016 के 29.8
  प्रतिशत से घटकर 25.9 प्रतिशत तक नीचे आ गया है।
- तमिलनाडु में भी घाटे में कमी आई है, जो वित्तीय वर्ष 2015-2016 के 20.39 प्रतिशत से घट कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14.53 प्रतिशत तक हो गया है।
- इसी तरह राजस्थान ने हानि को पिछले वर्ष के 27.3 प्रतिशत से घटाकर 23.6 प्रतिशत तक तथा उत्तर प्रदेश ने 33.84 प्रतिशत से घटाकर 30.21 प्रतिशत किया है।
- वित्तीय वर्ष 2016-2017 में हरियाणा में विद्युत की खरीद लागत में भी कमी आई है। यह पिछले वर्ष के प्रति यूनिट 5.05 रुपए से घटकर 5.01 रुपए हो गई है।
- सरकार के बयान में यह कहा गया है कि 30 सितंबर, 2015 को सभी सरकारी स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों का कुल कर्ज़ 3.95 लाख करोड़ था।
- 26 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश, जो उदय योजना में शामिल हो गए हैं, उनका कुल बकाया ऋण 3.82 लाख करोड़ था।
- अब तक 2.32 लाख करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी किये गए हैं। उदय योजना के तहत राज्यों के लगभग 86 प्रतिशत ऋण के बॉन्ड अब तक जारी किये गए हैं।